साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 03-09 जनवरी 2022, वर्ष-7, अंक-40

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

सोयाबीन की फसल से मप्र के किसानों का मोहभंग, बीते खरीफ के सीजन में लगभग 10 लाख हेक्टेयर रकबा घटा

कई प्रदेशों की कंपनियां सीधे किसानों से सौदा कर उठा रहीं माल

बासमती की महक पर मुग्ध किसान

संवाददाता। भोपाल

सोयाबीन उत्पादक राज्यों में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश के किसानों का अब इससे मोहभंग होता जा रहा है। कीट प्रकोप, अफलन और घटते उत्पादन से निराश किसानों को बासमती चावल की महक ने मुग्ध कर दिया है। किसान सोयाबीन का साथ छोड़कर बासमती धान उगाने की राह पर बढ़ रहे हैं। बीते खरीफ सीजन में ही सोयाबीन का रकबा मध्य प्रदेश में जहां करीब दस लाख हेक्टेयर घटा, वहीं बासमती का करीब इतना ही बढ़ा है। यहां के बासमती की महक उत्तर प्रदेश और पंजाब के निर्यातकों के जरिये विदेश में पाकिस्तानी बासमती को टक्कर दे रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते दो-तीन वर्षों से अन्य प्रदेश के प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों द्वारा प्रदेश का 80 से 90 लाख क्विंटल बासमती धान खरीदा जा रहा है। बढ़ती मांग और कम लागत में ज्यादा लाभ देकर बासमती किसानों को भी समृद्ध बना रहा है।

13 जिलों में बढ़ा रकबा

प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के करीब 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में बीते खरीफ सीजन में बासमती की फसल ली गई। ये जिले कभी सोयाबीन उत्पादक माने जाते थे।

उद्योगों को मिली संजीवनी

प्रदेश के बासमती की बढ़ती मांग ने औद्योगिक समूहों को भी आकर्षित किया है। रायसेन के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में दावत फूड्स और मैजेस्टिक राइस जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट संचालित हो रहे हैं। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की मिलर कंपनियों के प्रतिनिधि यहां किसानों से सीधे सौदा कर माल उठाते हैं।

मप्र की देश में धाक

प्रदेश की पांच मंडियों में 2014-15 से 2019-20 तक बासमती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रसंस्करणकर्ताओं ने खरीदा है। देश के कुल बासमती निर्यात में मध्य प्रदेश की भागीदारी 25 प्रतिशत है।

अमेरिका, इंग्लैंड में निर्यात

डीजीसीआईएस की वेबसाइट के अनुसार मंडीदीप के कंटेनर डिपो से बीते वर्षों में बासमती चावल का खाड़ी देशों के अलावा आस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड निर्यात हुआ।

जीआई टैग की लड़ाई जारी

प्रदेश के 13 जिलों में बासमती धान की खेती होती है, लेकिन जीआई टैग नहीं होने से उचित मूल्य नहीं मिलता। सरकार ने टैग के लिए आवेदन किया था, मद्रास हाईकोर्ट में अभी केस है।

दो वर्ष में बढ़ा बासमती और घटा सोयाबीन

फसल	वर्ष 2019-20	2020-21
सोयाबीन	64.99	56.64
बासमती	34.04	42.25

कृषि विभाग के अनुसार रकबा लाख हेक्टेयर में

विदेश में खाद्य सामग्री के गुणवत्ता के मापदंड कड़े हैं। पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश का बासमती ही निर्यात किया जाता था। मध्य प्रदेश का बासमती सभी मापदंडों पर खरा उतर रहा है, इसलिए इन प्रदेशों के निर्यातक यहां से धान ले जाकर अपने टैग पर निर्यात करते हैं।
राजेंद्र बाधवा, प्रबंध निदेशक, दावत फूड्स लिमिटेड, मंडीदीप

नव वर्षः किसानों के खाते में प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर किए 20 हजार करोड़

किसानों पर 'धनवर्षा'

संवाददाता, भोपाल।

नव वर्ष के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त 10.09 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर की। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में 20,946 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने किसानी उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। साथ ही मोदी ने 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अवशेषों से बायो फ्यूल बनाने के लिए देशभर में कई नई यूनिट लगाई जा रही हैं। सात साल पहले देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था। आज वही उत्पादन 340 करोड़ लीटर से भी ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को नई धार देने वाला है। इधर, मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल ने नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त में देश के 11.37 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए हृदय से आभार, अभिनंदन। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र से देश को नई ऊर्जा दी है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शिखर प्राप्त कर रही हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी सहित कई प्रभावशाली योजनाएं जारी हैं। उनके नेतृत्व में मप्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए अंकुर अभियान के अंतर्गत पौधरोपण एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के आपके संकल्प की सिद्धि में मप्र अपना हरसंभव योगदान देगा।

मप्र में मिलती दस हजार सम्मान निधि

किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में 6000 रुपए ट्रांसफर करती है। स्कीम के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों के किसानों को पीएम सम्मान निधि तो छह हजार मिलती है, लेकिन मप्र के किसानों को सबसे ज्यादा दस हजार मिलती है। इसमें चार हजार रुपए राज्य सरकार दे रही है।

सीएम शिवराज ने लिया संकल्प

प्राकृतिक खेती को देंगे बढ़ावा

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के किसानों की उन्नति के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4 हजार प्रति वर्ष व जीरो ब्याज पर कर्ज व कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। उनके मार्गदर्शन में मप्र में विगत कई वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मप्र में 16 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है और इसका निर्यात 2020-21 में ढाई हजार करोड़ से अधिक का हुआ है। मप्र यह संकल्प लेता है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में किसानों के साथ संवाद कर हरसंभव उपाय एवं नवाचार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

कृषि मंत्री कमल पटेल बोले

लाभ का धंधा बनेगी खेती

इधर, मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नया वर्ष 2022 किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है। घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली है। देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, उनके लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश के एक पात्र किसान परिवार को वर्ष में 10 हजार रुपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। यह राशि हमारे छोटे किसानों के लिए जीवनदायिनी है। कर्जदार से बचाने वाली है। कर्ज से मुक्त करने वाली है। नव वर्ष पर प्रधानमंत्री ने मप्र सहित देशभर के 10.09 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 20,946 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। मध्यप्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सीएम के नेतृत्व में हम मध्यप्रदेश के किसानों को 04 हजार रुपए राशि दे रहे हैं। इससे हमारे किसान और समृद्ध होंगे।

अब घटिया बीज से मप्र के किसानों को मिलेगी निजात

किसानों के पास होगी अब बीज की 'कुंडली'

संवाददाता। भोपाल

महंगा बीज खरीदने के बाद भी फसल खराब होने की समस्या से किसानों को जल्द ही निजात मिलेगी। इसके लिए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसमें राज्य बीज विकास निगम से जो बीज किसानों को सहकारी समितियों, विक्रय केंद्र, विपणन संघ या सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जाएगा, उसके बैग पर क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस कोड) होगा। इस कोड को चेको एप के माध्यम से देखने पर बीज की पूरी कुंडली पता चल जाएगी। बीज किस किसान द्वारा उत्पादित है और यह बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित है या नहीं, आदि की जानकारी मिलेगी। इसके अंकुरण की क्षमता सहित अन्य जानकारी किसान पता कर सकेंगे। इससे बीज की गुणवत्ता तो सुनिश्चित होगी ही प्रमाणित बीज के नाम पर होने वाली गड़बड़ी पर भी रोक लगेगी। बीज निगम डेढ़ लाख क्विंटल से अधिक चना, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मसूर, अलसी, अरहर आदि के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराता है। गौरतलब है कि प्रदेश में अक्सर घटिया बीज की आपूर्ति की शिकायतें किसान करते हैं। सहकारी समितियों को बीज निगम द्वारा बीज की आपूर्ति की जाती है जो सदस्य किसानों को बतौर सामग्री ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

अब साख पर नहीं लगेगा बटटा

बीज की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले प्रश्नों से निगम की साख भी प्रभावित होती है और किसानों को नुकसान भी होता है। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि बीजों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। निगम किसानों से बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत दिए गए बीज को वापस लेकर किसानों को विक्रय करता है। अब जो भी बीज विक्रय किया जाएगा, उसके बैग पर क्यूआर कोड होगा। गुणवत्ता का पता लगाने के लिए निगम ने चेको एप तैयार किया है।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। हम जो बीज किसान को देते हैं, वो पूरी तरह से प्रमाणित है, इसकी जानकारी किसान स्वयं ले सकेगा। इसके लिए प्रत्येक बीज के बैग पर एक क्यूआर कोड होगा, जिसके माध्यम से किसान यह पता लगा सकेगा कि जो बीज उसने लिया है, उसे किस किसान ने उत्पादित किया है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और वो बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित है या नहीं। इससे बीज को लेकर जो शिकायत आती है, वो दूर हो जाएगी।
प्रीति मैथिल, प्रबंध संचालक, कृषि और निगम

मध्य प्रदेश में अब 15.14 लाख टन धान की खरीद की गई

धान खरीदी में छठवें नंबर पर एमपी

-अक्टूबर-दिसंबर में धान खरीद 443.49 लाख टन तक पहुंची

संवाददाता। भोपाल

खाद्य मंत्रालय ने दावा किया है कि अक्टूबर 2021 से शुरू हुए चालू विपणन वर्ष में सरकार की धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद अब तक 443.49 लाख टन तक पहुंच गयी है। इसमें धान की अधिकतम खरीद पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना से की गई है। इसमें से चालू विपणन वर्ष में अक्टूबर से 26 दिसंबर के दौरान पंजाब से करीब 186.85 लाख टन, हरियाणा से 55.30 लाख टन, तेलंगाना से 52.88 लाख टन, छत्तीसगढ़ से 47.20 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 38 लाख टन, मध्य प्रदेश से 15.14 लाख टन धान की खरीद हुई है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 86,924.46 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 47 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। विपणन वर्ष 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान, सरकार ने 1,68,848.65 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ 894.32 लाख टन धान की खरीद की थी। इससे 1.31 करोड़ किसान लाभान्वित हुए थे। धान की खरीद अक्टूबर 2021 में शुरू हुई और सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। एमएसपी पर धान की यह खरीद सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ-साथ राज्य संगठनों द्वारा की जाती है।

5वें नंबर पर यूपी

तीसरे नंबर पर तेलगान है जहां 784268 किसानों से 5288206 मीट्रिक धान धान की खरीद हुई और 10364.88 लाख रुपए की एमएसपी का भुगतान हुआ है। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है जहां 1246022 किसानों से 4720020 मीट्रिक टन के बदले 9251.25 लाख रुपए की एमएसपी मिली है। पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है 507349 किसानों से 380172 मीट्रिक धान के बदले 7451.41 लाख रुपए की एमएसपी मिली है।

धान खरीद करने वाले टॉप 5 राज्य

राज्य	धान खरीद	लाभार्थी किसान	एमएसपी मूल्य (करोड़ रु)
पंजाब	18685532	924299	36623.64
हरियाणा	5530596	310083	10839.97
तेलंगाना	5288206	784268	10364.88
छत्तीसगढ़	4720020	1246022	9251.25
उत्तर प्रदेश	380172	507349	7451.41

आगे बढ़ता एमपी

वहीं मध्यप्रदेश की बात की जाए तो अभी तक खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत 26 दिसंबर, 2021 तक 47.03 लाख से ज्यादा किसानों से 86,924.46 करोड़ रुपये के एमएसपी पर 443.49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है।

47.03 लाख किसान लाभान्वित

देश में 26 दिसंबर तक कुल 443.49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसमें से पंजाब में अब तक सबसे अधिक 186.866 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 26 दिसंबर तक देशभर में 86,924.46 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 443.49 एलएमटी धान की खरीद हुई है, जिससे 47.03 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

अभी पंजाब अव्वल

खरीफ विपणन सीजन में 26 दिसंबर तक की बात करें तो पंजाब में 924299 किसानों से 18685532 मीट्रिक धान धान की खरीद हुई, जिसमें किसानों को 36623.64 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है जहां 310083 किसानों से 5530596 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है और एमएसपी के 10839.97 लाख रुपए का भुगतान हुआ है।

कूनो सेंचुरी में चीते आने के बाद बढ़ेगी विदेशी पर्यटकों की संख्या

होमस्टे से आत्मनिर्भर होंगे सहरिया

इंसाफ कुरैशी। श्योपुर

कूनो सेंचुरी में चीते आने के बाद क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ेगी। देश-विदेश से सैलानी अफ्रीकी चीतों को देखने के लिए श्योपुर आएंगे। इसका असर श्योपुर की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक रूप से पड़ना तय है। थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर इस दिशा में काम किया जाए तो क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या पर भी बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकती है। पर्यटकों को ठहराने के लिए वैसे तो रेस्टहाउस और रिसॉर्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन होम स्टे योजना के तहत पर्यटकों को वनांचल में प्राकृतिक वातावरण के बीच ठहराने पर प्रशासन विचार करें तो यह सहरिया जनजाति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यटकों को लुभाने के लिए बेहद अच्छी और सफल पहल साबित हो सकती है। विदेशी सैलानी भारत में ठहरने के लिए नेचुरल माहौल अधिक पसंद कर रहे हैं।

उनकी इस पसंद को देखते हुए केंद्रीय पर पर्यटन मंत्रालय ने होम स्टे योजना शुरू की है। इसी योजना के तहत लोगों को अपने घरों में ऐसे आवास तैयार करने को कहा जा रहा है, जिसमें वह खुद रहने के साथ-साथ विदेशी मेहमानों को ठहरा सके। इसके लिए संबंधित को होटल की तरह किराया भी दिया जाता है। होम स्टे योजना के तहत आवास बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत गृह स्वामी के साथ रहने वाले विदेशी सैलानी उनके परिवार के द्वारा रोजाना की जाने वाली गतिविधियों को शेयर भी करते हैं। होम स्टे योजना की शर्त में यह शामिल है कि सैलानी गृह स्वामी के साथ भोजन व्यवस्था में एक से ही रसोई का उपयोग और उनके साथ खेती-बाड़ी जैसे काम में हाथ बटाने का काम भी कर सकते हैं। विदेश से आए सैलानी भारती संस्कृति से रूबरू हो इसका उद्देश्य होम स्टे योजना तहत पूरा किया जाता है। कराहल विकासखंड के वनांचल में रहने वाली सहरिया जनजाति को होम स्टे योजना से जोड़कर सैलानियों को वनांचल के प्राकृतिक वातावरण में साथ रहने के लिए नया और बेहद सफल होने वाला प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आदिवासियों की झोपड़ियों को थोड़ा विकसित करना, आंगन को आकर्षक बनाने की जरूरत है।

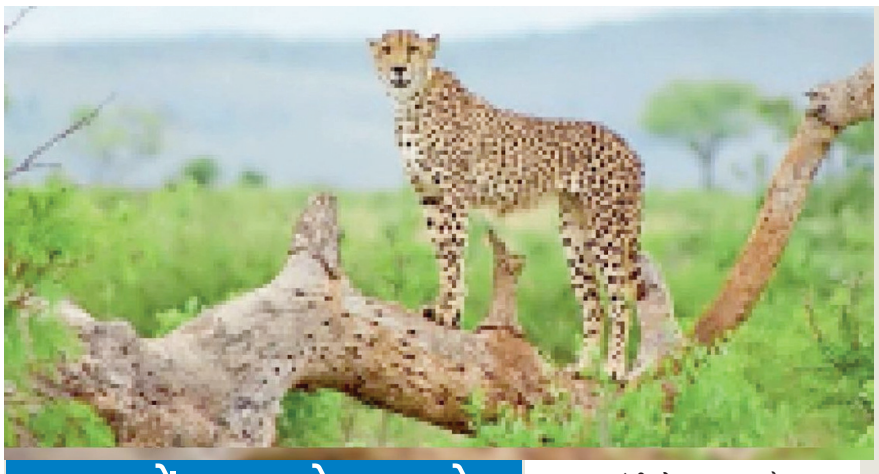

जयपुर में सफल हो रहा प्रयोग

विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति से रूबरू होने और यहां के नेचुरल वातावरण को महसूस करना चाहते हैं। इस तरह से कुछ होटल मालिकों ने इस तर्ज पर अपनी होटलों को विकसित किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एक फाइव स्टार होटल इसी तर्ज पर बनाया गया है। इस होटल में पक्के कमरे नहीं है, बल्कि घास पूस की झोपड़ियां बनाई गई हैं। झोपड़ी में रहने के लिए विदेशी सैलानी हमेशा वहां आते रहते हैं। राजधानी की चकाचौंध के बीच कृतिम रुप से तैयार किए गए वातावरण के उलट नेचुरल वातावरण में सैलानियों को ठहरने की सुविधा दी जाए तो यह प्रयोग ना सिर्फ बेहद सफल होगा, बल्कि सहरिया जनजाति को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है।

प्रकृति का वातावरण लुभाएगा

होम स्टे योजना के तहत विदेशी सैलानियों को वनांचल में बनी झोपड़ियों में सहरिया जनजाति के परिवार के साथ ठहराने पर विदेशी सैलानियों सहरिया जनजाति के रहन सहन से वाकिफ होंगे। दूसरे वनांचल में चारों ओर बिखरी प्राकृतिक छटा पर्यटकों को बार-बार यह लाने के लिए प्रेरित करेंगी। इस काम में आमेट का किला, आम खो, डोब कुंड ऐसे स्थल है जो पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के माध्यम से कई बार विदेशी समाजसेवियों ने जंगल में आकर सेवा की हैं और उन्हें वनांचल में रहना बहुत भाया है। अगर सहरिया जनजाति को होम स्टे योजना से जोड़ा जाए तो यह इन गरीब आदिवासियों की आजीविका को बढ़ाने एवं सैलानियों को आकर्षित करने में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

जयसिंह जादौन, समाजसेवी, श्योपुर

कूनो में चीतें बसाहट के साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने एनआरएलएम के माध्यम से महिला समूहों को होटल संचालन का काम सौंपा हैं। सहरिया जनजाति को होम स्टे योजना से जोड़ने के साथ सहरिया युवाओं को प्रशिक्षण देकर गाइड बनाने का काम भी करेंगे।

शिवम वर्मा, कलेक्टर, श्योपुर

एक साल से चल रही जांच, 30 सरपंच और सचिव बने आरोपी

1200 पंचायतों में 20 करोड़ का घोटाला

संवाददाता। भोपाल

राज्य सरकार जहां एक ओर गरीबों और पिछड़े वर्ग को लाभ दिलाने के लिए पसीना बहा रही है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारों की अनदेखी से पात्र हितग्राही योजनाओं की लाभ से वंचित हो रहे हैं। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अभी पुलिस 1200 पंचायतों की जांच कर रही है। दरअसल, पंच परमेश्वर योजना में 20 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में एक साल पहले हुई थी। इसकी जांच जारी है। एक साल में पुलिस ने 15 पंचायतों की जांच पूरी कर 30 सरपंच और सचिवों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 15 पंचायतों में डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार सामने आया है। गौरतलब है कि लगभग एक साल पहले लोकायुक्त में कट्ठीवाड़ा, आलीराजपुर, सोंधाय, जोबट, उदयनगर की 1200 पंचायतों की शिकायत हुई थी। शिकायत में बताया गया था कि यहां पंच परमेश्वर योजना में होने वाले विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पंचायतों के सरपंच और सचिवों ने मिलकर लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का घोटाला किया है। जांच लोकायुक्त के डीएसपी एसएस यादव को दी गई थी। इनमें से अब तक उन्होंने उदयनगर की 11 और चंद्रशेखर आजाद नगर भाबरा की 15 पंचायतों की जांच पूरी कर ली है। इसमें लगभग डेढ़ करोड़ की राशि का घोटाला सामने आया है। इसके बाद साल के अंत में लोकायुक्त पुलिस ने इन पंचायतों के 30 सरपंच और सचिवों के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। डीएसपी ने बताया कि एक-एक कर सभी पंचायतों की जांच की जा रही है। जिसमें भी भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं, उसमें केस दर्ज किया जा रहा है। एक-दो माह में कुछ और पंचातयों के सरपंच और सचिवों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि लोकायुक्त की कार्रवाई से भ्रष्ट सरपंच और सचिवों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस कह रही है कि वसूली के साथ जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी।

देश में हर साल गांवों में 50 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा

ड्रोन से उड़ान भरेगी कृषि

» ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि और एमएसएमई में होगा फायदा

संवाददाता। भोपाल/नई दिल्ली

किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार नई तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दे रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार अब कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। देश के कई भागों में ड्रोन की मदद से कीटनाशक व यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। जिससे बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल करने पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। गडकरी ने यह बात नागपुर में एग्रोविजन प्रदर्शनी के समापन अवसर पर कही। केंद्रीय नितिन गडकरी ने बताया कि ड्रोन कृषि और एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है और ड्रोन के इस्तेमाल से इन दोनों सेक्टरों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के साथ कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर नीति तैयार करने पर काम करने के लिए चर्चा की है। ड्रोन से ग्रामीण इलाकों में संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ड्रोन एक वर्ष में 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

खेती की लागत होगी कम

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में ड्रोन का उपयोग शुरू कर दिया है और कीटनाशकों के मशीनीकृत छिड़काव में कटौती की है। जब ड्रोन खेतों में कीटनाशक व तरल यूरिया का छिड़काव करेगा तो पूरी फसल पर समान मात्रा में छिड़काव होगा। साथ ही समय भी कम लगेगा और मानवीय श्रम की लागत में बचत होगी।

छह और डेढ़ लाख में ड्रोन

गडकरी ने बताया कि किसानों को ड्रोन 6 लाख और डेढ़ लाख में उपलब्ध हो सकेगा। लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले ड्रोन की कीमत करीब छह लाख होगी, जबकि एथेनॉल ईंधन से चलने पर इस मानव रहित हवाई वाहन की कीमत लगभग 1.5 लाख होगी। ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उन्हें संचालित करने के लिए बड़ी संख्या में पायलटों की आवश्यकता होगी।

किसान बनेगा ऊर्जादाता

समारोह के दौरान गडकरी ने कहा कि देश का किसान अब अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता भी होगा। देश में अब दोपहिया व चार पहिया वाहन शत-प्रतिशत इथेनॉल से चलेंगे जो किसान का तैयार किया हुआ है। इससे देश के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और प्रदूषण कम होगा। पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी।

ड्रोन संचालन के लिए एसओपी जारी

कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी कर दिया है। पिछले दिनों एसओपी जारी करते समय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के परामर्श के बाद ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसमें ड्रोन के प्रभावी एवं सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश शामिल हैं। खेती में ड्रोन का उपयोग फसल के दबाव की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पैदावार की भविष्यवाणी, खरपतवार नाशक, उर्वरक तथा पानी जैसी सामग्रियों का वितरण आदि में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के युवा इंजीनियर अभिनव ने विकसित की खास ड्रोन

अब ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव के साथ किसान करेंगे खेत में बोवनी

संवाददाता। भोपाल

खेती को लाभकारी बनाने के लिए देश के कृषि वैज्ञानिक लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक के साथ कृषि उपकरण भी बनाए जा रहे हैं। इन सबमें तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लागत कम की जा सके। साथ ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ कृषि के परंपरागत तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। जबलपुर के युवा इंजीनियर भी बीते कई सालों से कृषि के नए-नए तरीकों को विकसित करने में जुटे हैं। इस बार इस युवा इंजीनियर ने बुवाई के लिए ड्रोन का उपयोग करके हर किसी को हैरान कर दिया है। ट्रैक्टर और सीडड्रिल की मदद से खेतों में बोवनी करने का तरीका अब बदल गया है और आने वाले समय में ड्रोन की मदद से खेतों में बीज बोया जाएगा। जबलपुर के माढ़ोताल क्षेत्र में रहने वाले अभिनव ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो 30 किलो तक वजन उठाने की क्षमता रखता है। ड्रोन में एक टैंक फिट किया गया है, जिसमें धान या गेहूं के बीज को भरा जाता है और फिर खेत में उड़ाकर बीज को क्यारियों में छिड़का जाता है। अभिनव ने बीएचयू के वैज्ञानिकों के आग्रह पर इसका प्रयोग मिर्जापुर के खेतों में करके दिखाया।

एक बार में 6 हेक्टेयर खेत कवर करता है ड्रोन

किसान को ड्रोन ऑपरेट करने का ज्ञान होना जरूरी है। मोबाइल या टैबलेट में गूगल मैप की मदद से खेत का नक्शा फीड किया जाता है, जिसके बाद एक बार स्टार्ट करने पर यह बीज या बैटरी खत्म होने तक खुद ही खेत के एरिया के अनुसार बोवनी करता रहता है और बीज या बैटरी खत्म होने के बाद वापस अपनी जगह पर ऑटोमेटिक लैंड होकर रुक जाता है। अभिनव ने इस ड्रोन को देश के किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया है।

आधुनिक कृषि में क्रांति

पांच साल की मेहनत और किसानों की जरूरत के मुताबिक इसकी डिजाइन और क्षमता का विकास किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा खेती-किसानी में उपयोग में आने वाला ड्रोन है, जिससे एक बार मे तीस लीटर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ड्रोन 6 हेक्टेयर का कवरेज देता है। यह कहा जा सकता है कि कम समय और कम खर्च में ड्रोन टेक्नोलॉजी से आधुनिक कृषि में क्रांति आ रही है।

खेती का भविष्य ड्रोन

अभिनव ने बताया कि यूपी के अधिकतर जिलों में धान की कटाई होने के बाद ठंड का मौसम आ जाता है, जिससे वहां के खेत सूख नहीं पाते और ट्रैक्टर सीडड्रिल से गेहूं की बोवनी करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से गेहूं के बीज का छिड़काव किया जाता है, जिसमें कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। इस समस्या की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने ड्रोन को मॉडिफाई किया, जिसमें टैंक के नीचे सीडड्रिल के जैसे छेद वाली फनल यानी चाड़ी लगाई और इसी के माध्यम से बीज नीचे गिरता है। इस डेमो के दौरान सैकड़ों किसान और कृषि वैज्ञानिक भी खेत मे मौजूद थे, जिन्होंने इसे खेती का भविष्य बताया।

लहसुन की फसल चौपट, पुरानी के भी नहीं मिल रहे भाव

मल्हारगढ़। लहसुन को लेकर किसान काफी परेशान हैं। जहां एक ओर किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं लहसुन की फसल में फफूंद व दीमक लगने से जिस आकार में लहसुन की गाठ बनना चाहिए व नहीं बनी। कांग्रेस नेता परशुराम सिसौदिया, मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिला कांग्रेस के महामंत्री रामचन्द्र करुण, धुंधड़का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल आदि ने ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लहसुन के खेतों में जाकर किसानों से चर्चा की पिपलीया विशनिया के किसान देवीलाल पाटीदार ने बताया कि मैंने 2 बीघा में लहसुन बोवनी की थी। डेढ़ माह बाद भी लहसुन का गाठिया नहीं बन पाया है। कई महंगी दवाइयों के छिड़काव के बाद भी फसल पर कोई असर नहीं हुआ है और लगभग 75 हजार रुपए का अभी तक खर्चा हो गया है। लागत मूल्य तो दूर की बात मेहनत की राशि भी नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि विगत दिनों मंदसौर कृषि उपजमंडी में उज्जैन जिले के एक किसान ने लहसुन के भाव नहीं मिलने के कारण लहसुन में आग लगा दी थी। इधर, कांग्रेस नेता परशुराम सिसौदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार किसान विरोधी है। इनकी सारी योजनाएं पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने की बनती हैं। यह किसानों का शोषण करते हैं। कांग्रेस शासन में किसानों को उपज का वाजिब दाम मिल रहा था।

-किसानों को अपनी उपज का नहीं मिल रहा वाजिब दाम

बकरी के दूध का उभरता बाजार

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

वैश्विक बाजार में भारत 5.6 मिलियन टन बकरी का दूध उत्पादन करता है, जो कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। दुनियां में भारत बकरी दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। वैश्विक बकरी दूध का वर्ष 2018 में 8.5 बिलियन डालर का बाजार था और यह 2026 तक 11.5 बिलियन डालर के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है। देश के कुल दूध उत्पादन में बकरी के दूध की लगभग 3 से 4 प्रतिशत तक हिस्सेदारी है। गुणवत्ता के अनुसार बकरी के दूध का रासायनिक संगठन लगभग मानव दूध के समान ही है। भारत में बकरियों को निर्धनों की आजीविका का साधन माना जाता है। साथ ही गरीबों की गाय के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने भी बकरी के दूध के महत्व को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत तौर पर इसका दुग्ध उपयोग के लिए अपनाया था।

यूरोपियन देशों में इसे नवजात शिशुओं की मां (नर्स) के रूप में पाला जाता है। मां का दूध उपलब्ध न होने की स्थिति में बकरी के दूध को पीने की सलाह दी जाती है। अन्य जानवरों के बच्चों को भी बकरी के दूध पर आसानी से जिंदा रखकर पाला और बचाया जा सकता है। यह सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध होने और अपनी विशेषताओं, उपयोगिताओं व गुणों के कारण एक औषधी का कार्य करता है। जिस तरीके से धीरे-धीरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर अर्द्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्र के लोगों में बकरी पालन के प्रति जिज्ञासा, जागरूकता और रुझान बढ़ा है। उसको देखते हुए आने वाले कुछ ही वर्षों में बकरी पालन एक उभरते हुए व्यवसाय का रूप ले सकता है। कम समय, कम श्रम और कम पूंजी के साथ इस व्यवसाय को शुरू करके कुछ ही वर्षों के अंदर बड़ा रूप दिया जा सकता है। देश की भौगोलिक परिस्थितियों और बदलते जलवायु परिवर्तन को देखेते हुए बकरी को एक भविष्य का पशु कहना गलत नहीं होगा।

दुनिया में आज जहां बकरा मांस की मांग सर्वाधिक है, वहीं बकरी के दूध के गुणों को देखते हुए धीरे-धीरे इसकी मांग पैदा होना शुरू हो चुकी है। देश के कई राज्यों में अलग से बकरी के दूध का बाजार खड़ा होना भी शुरू हो चुका है। देश में अभी तक बकरी के दूध का अलग से कोई बाजार नहीं रहा है। अधिकांशत: बकरी का दूध गाय-भैस के दूध के साथ ही मिला कर बिक्री होता रहा है, लेकिन देश के कई हिस्सों में धीरे-धीरे अलग से बकरी के दूध का बाजार खड़ा होना शुरू हो चुका है। इससे बकरी पालकों को उनके दूध का उचित भाव मिलने के साथ ही जरूरतमंद उपभोक्ताओं को शुद्ध बकरी का दूध सुलभ हो पा रहा है। कई प्रमुख बीमारियों में बकरी के दूध की उपयोगिता सिद्ध होने के कारण देश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ वर्षों में इसके दूध की मांग तेजी से बढ़ी है। आज दिल्ली, बंगलरु से लेकर लखनऊ तक में बकरी का दूध खरीदा और बेचा जाने लगा है। राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे राज्यों के कुछ जिलों में भी बकरी का दूध खरीदा-बेचा जा रहा है। कुछ प्राइवेट संस्थान, एनजीओ, एफपीओ एवं कॉपरेटिव दुग्ध संघों द्वारा इस दिशा में कार्य करना शुरू किया गया है। यह बकरी पालकों से दूध खरीद कर उसे पाश्चुरीकृत करने के साथ ही पैकिंग करके बिक्री कर रहे हैं। हांलाकि अभी यह कार्य प्रारंभिक स्तर पर ही हो रहा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में अच्छी पहल की है। राज्य के इंदौर और जबलपुर दुग्ध संघों के माध्यम से इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में ग्रामीण-आदिवासी बकरी पालकों से 50 से लेकर 70 रुपए प्रति लीटर की दर पर बकरी दूध खरीदने की शुरुआत की गई है।

बकरी के इस दूध को प्रोसेसिंग करके 200 एमएल की बोटल में 30 रुपए की दर पर आम उपभोक्ताओं को बिक्री भी किया जा रहा है। इससे बकरी पालकों को दूध की अच्छी कीमत मिलना शुरू हुई है। वहीं बकरी के दूध के शौकीन एवं जरूरतमंद लोगों को शुद्ध बकरी का दूध मिल पा रहा है। जरूरत इस बात की है कि अन्य राज्यों में दुग्ध संघों को भी इस दिशा में आगे आने की। अमूल ब्रांड जैसा इस दिशा में पहल करता है, तो बकरी के दूध के बाजार को नई दिशा मिल सकेगी। इससे बकरी पालन के प्रति आम ग्रामीणों में और अधिक रुझान पैदा होगा। क्योंकि अभी तक बकरी सिर्फ मांस के लिए ही बिक्री हो रही थी। अब दूध, मांस, रेसा और खाल सब कुछ बिक्री होने के चलते बकरी पालन और अधिक मुनाफे का धंधा बनकर उभर सकेगा। बकरी के दूध में कैप्रोइक, कैप्रीलिक तथा कैप्रिकवसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है। इन्हीं वसीय अम्लों की मात्रा के कारण बकरी का दूध हृदय से संबंधित रोगों, गुर्दे तथा पित्ताशय से संबंधित विकारों एवं महिलाओं में प्रदर रोग के उपचार में कारगर सिद्ध हुआ है। बकरी का दूध अत्यधिक पौष्टिक होता है। इसमें पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम सहित सभी आवश्यक विटामिन और खनिज लवणों की प्रचुरता होती है। यह रक्तचाप के स्तर को कम करने, चयापचय को बढ़ाने, अच्छे हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने, तंत्रिका कार्य प्रणाली में सुधार करने के साथ ही लाभदायक आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से बकरी का दूध सेवन करने से डेंगू जैसे वायरल रोगों में रक्त प्लेटलेट काउंट में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एनीमिया, अस्थमा, एक्जिमा, मैग्नीशियम की कमी वाले रोगों, पाचन रोगों और त्वचा विकारों में भी मदद करता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, जैसे हृदय संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हड्डी रोगों आदि के प्रति बढ़ती लोगों की फिक्र से बकरी दूध की मांग बढ़ी है। लैक्टोज असहिष्णु व्यक्तिओं का झुकाव भी बकरी दूध के प्रति होने से बाजार को और अधिक उत्प्रेरित कर रहा है। बकरी के दूध पर आधारित शिशु फॉर्मूला अपनी उच्च पोषण सामग्री के कारण आकर्षण पैदा कर रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद से बकरी दूध की मांग बढ़ी है। बाजार में उपलब्ध बकरी दूध उत्पादों में पाश्चुरीकृत दूध, दही, पनीर, दूध पाउडर, शिशु फॉर्मूला आदि शामिल है। इसके अलावा साबुन से लेकर सौन्दर्य प्रसाधन तक बनाने में बकरी के दूध की काफी मांग बढ़ी है। पोषण की दृष्टि से बकरी दूध को लगभग गाय के दूध के समतुल्य ही माना जाता है, लेकिन कुछ भौतिक गुणों में अंतर के कारण यह मनुष्यों की पाचन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्रभाव शाली है।

एक्जिमा, अस्थमा, गैस संबंधी परेशानी, कब्ज अथवा पाचन संबंधी विकारों में गाय की तुलना में बकरी का दूध ज्यादा लाभदायक माना जाता है। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि गाय के दूध के विपरीत बकरी का दूध पेट में सूजन कम करता है। यह दिल का स्वस्थ्य रखता है। दिल के दौरे और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे हृदय रोगों के होने की संभावना को कम करता है। बकरी के दूध में प्रोटीन एवं कैल्शियम का अच्छा प्रतिशत होता है, जो वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के साथ ही हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बकरी दूध के प्रति लोगों में पैदा हो रही जागरूकता और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के कारण बकरी दूध का एक नया बाजार खड़ाहोना शुरू हो चुका है। इसके चलते भविष्य में इसका लाभ बकरी पालकों को मिलना तय है।

भारतीय कृषि, खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार के थाईलैंड से दो सबक

भारत किसानों का देश है। दुनिया के कई विकासशील और अविकसित देश भी किसानों के देश हैं। एक उदाहरण थाईलैंड है, जो दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक देशों में से एक है। 1960 के दशक में, जब भारत में खाद्य उत्पादन की कमी थी, थाईलैंड ने चावल के बोरे भेजकर मदद की। आज हम फिर से थाईलैंड के आभारी हैं, क्योंकि हम वहां से दो नए सबक सीख सकते हैं। पहला है कॉफी, चाय और गन्ने जैसी नकदी फसलों के माध्यम से पिछड़ी जनजातियों का उत्थान। उत्तरी थाईलैंड में रहने वाले शान जनजाति के विकास के लिए निजी उद्यमियों और थाईलैंड सरकार का साथ आना फायदेमंद साबित हुआ है। शान जनजाति थाईलैंड, बर्मा, चीन और लाओस में फैली हुई है। कम संख्या होने के कारण इन सभी देशों में इस जनजाति की उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा यह पूरा क्षेत्र हमारे देश के दंडकारण्य या पूर्वोत्तर की तरह घने जंगल से आच्छादित है।

आशीष कुमार सिंह,
-लेखक: वर्तमान में रूस की नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी (एचएसइ) से राजनीति की पढाई कर रहे हैं, ये उनके निजी विचार हैं।

इन जंगलों का शोषण अलगाववादी, आतंकवादी, हथियार तस्कर और ड्रग डीलर करते हैं। आज भी यहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होने के कारण इस क्षेत्र को सीआईए द्वारा गोल्डन ट्राएंगल के नाम से जाना जाता है। अफीम से कॉफी-थाईलैंड मॉडल पिछले एक दशक में यहां आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। मुख्य कारण यह है कि थाईलैंड की सरकार ने इस क्षेत्र को कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त माना है। बर्मा की सीमा से लगा उत्तरी थाईलैंड का यह इलाका पहाड़ी है और यहां का तापमान साल भर ठंडा रहता है। यहां बारिश भी ज्यादा होती है। ये तीनों कारक कॉफी के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। दक्षिण थाईलैंड में कई वर्षों से कॉफी उगाई जाती है, इसलिए देश को पहले से ही कॉफी उगाने के बारे में सारी जानकारी है। शान जनजाति के वरिष्ठ नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि यह उनके कबीले के युवाओं को तस्करी और हिंसा से बचाने का एक तरीका है। इतना ही नहीं, कॉफी की खेती और निर्यात भी रोजगार का अच्छा स्रोत है। इस प्रयास में, थाई सरकार ने भूमि और सुरक्षा प्रदान की, और निजी निवेशकों ने पूंजी जुटाई ताकि फसल सफल हो सके। यह प्रयास पिछले दस वर्षों में बहुत सफल रहा है, और इस थाईलैंड मॉडल की चर्चा कई पश्चिमी और एशियाई देशों में की गई है। बर्मा और लाओस भी इस अध्याय का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अफीम की जगह कॉफी की खेती कर नए अवसर पाने की थाईलैंड की ये सफलता भारत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। हमारे देश में ऐसे ही वन क्षेत्र हैं जहां चाय और कॉफी की खेती की जा सकती है। इन क्षेत्रों के स्थानीय आदिवासियों को भी लाभ होगा, और इन क्षेत्रों, जो नक्सलवाद, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से ग्रस्त हैं, को भारत की आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। यह प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ वर्षों से चलाया जा रहा है।

दिल्ली में आधारित सोशल इंटरप्राइज आयनक्योर संस्था इस प्रयास को एक कदम और आगे ले जाने की योजना बना रहा है। न केवल चाय के उत्पादन को बल्कि वन औषधियों और वन संपदा की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कई बीमारियों को रोक सकता है, और भारत के भौतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बढ़ा सकता है। थाईलैंड में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन अब वहां कॉपी भी होने लगी है। 1990 के दशक में थाईलैंड सेक्स और ड्रग पर्यटन के लिए कुख्यात था। पुलिस की कार्रवाई से यह अवैध धंधा विश्व माफिया के कब्जे में आ गया।

फास्फेट अवषोषक: जैव उर्वरक अपनाए किसान फसलों का उत्पादन बढाएं

पौधों के वृद्धि एवं विकास तथा उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कुल सत्रह तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कार्बन, हाईड्रोजन एवं आक्सीजन पौधों के आधार तत्व हैं। शेष तत्वों को पौधों की अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण के आधार पर मुख्य रूप से दो समूहों में विभक्त किया गया है। जिसमें प्रथम समूह के अंतर्गत मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर आते हैं। द्वितीयक समूह के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे-बोरान, कापर, क्लोरीन, मैगनीज, मोलिब्डनम, जिंक, आयरन एवं निकिल आते हैं। पौधों को सबसे अधिक नत्रजन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे स्थान पर फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, जो मूलत: पौधों के जड़ों के विकास और उसकी मजबूती के लिए सहायक होते हैं। जिसके लिए हमारे किसान फॉस्फेट अवशोषक जैव उर्वरक (वाम) का प्रयोग करके मृदा के अंदर पाए जाने वाले अप्राप्त फॉस्फोरस तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के पौधों के अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देते हैं। उच्च वर्गीय पादप जडों एवं फफूंद तंतुओं के बीच सहजीवी सह-संबंध को माइकोराइजा का नाम दिया गया है। फाइको माई सिटीज फफूंद एवं अधिकतर फसलों के सह-संबंध से वाम का निर्माण होता है। वाम फॉस्फोरस घोलक जीवाणु से अलग होता है। क्योंकि यह अघुलनशील या अनुपलब्ध फॉस्फोरस को घुलनशील नहीं बनाता, बल्कि यह फॉस्फोरस, जिंक तथा अन्य पोषक तत्वों का स्वांगीकरण करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद यह पोषक पौधों की जड़ों को संक्रमित करके जड़ के अंदर फैल जाते हैं। विशेष प्रकार की संरचनाओं का रूप धारण कर लेते हैं। जिन्हें अरब सकल्स एवं बेसीकल्स कहते हैं। अरब सकल्स फफूंद से पोषक तत्वों को जड़ तंत्र में स्थानांतरित करने में सहायक होता है। जबकि बेसीकल्स जिनकी संरचना एक छोटी झिल्ली के थैली के समान होती है। फॉस्फोरस को फॉस्फोलिपिडस के रूप में संग्रहित कर लेती है। फॉस्फोरस के अलावा ये जिंक, कापर, आयरन, मैगनीज तथा सल्फर का भी संचयन कर लेते हैं। इनके प्रमुख लाभ इस पकार हैं, जैसे माइकोसइजा के कवक सूत्र मृदा में गहराई तक फैल कर शुष्क परिस्थितियों में पौधों के लिए जल की पूर्ति करते हैं। यह फंजाई नाशक पदार्थों का साब्र करते हैं, जो पाइथीयम राइजोक्टोनिया एवं फ्यूजोरियम फंजाई के लिए हानिकारक और पौधों के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार पौधों को हानिकारक रोगों से बचाता है। फ्रेचूयि औरेशिया नामक वैक्टीरिया अविलेय पोटश को विलेय करने में काफी सक्षम होते हैं। वाम के प्रयोग से फसलों के उत्पादन क्षमता में औसत 15-35 प्रतिशत वृद्धि होती है। फसलें जिनका कवक सह-संबंध होता है। जैसे गेहूं, मक्का, लघु, धान्य फसलें आलू, सोयाबीन, टमाटर, अंगूर, सेव, केला, गन्ना, तम्बाकू आदि हैं। वाम का उपयोग सभी फसलों जैसे दलहनी, चारे वाली, अन्नवाली फसलों आदि में किया जा सकता है। यह पोषक तत्वों जैसे-फास्फोरस, जिंक, कापर, पोटाश, एल्यूमिनियम मैंगनीज तथा मैग्नीशियम को सीधे मृदा से जड़ क्षेत्र में स्थानांतरित कर देता है। जिससे पौध आसानी के साथ अवशोषित कर लेते हैं। यह कुछ वृद्धि कारक पदार्थो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जिवोरालिन्स और विटामिन आदि का उत्पाद करके सहसंबंधी पौधों की वृद्धि को बढ़ा देता है। यह जल एवं पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित करके पौधों को प्रदान करता है। तथा पौधों से अपने लिए भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है, जो कि सहजीविता का उदाहरण है। प्रयोग की मात्रा-वाम का प्रयोग एक एकड़ रोपाई के लिए बनाई गयी नर्सरी वेड के लिए 2-4 किग्रा कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। खेतों में सीधी बोवनी के लिए 6-12 किग्रा कल्चर/प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। 15-20 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल बीच के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे-वाम को तेजधूप एवं गर्मी से दूर रखना चाहिए। वाम का प्रयोग सुबह या शाम के समय करना चाहिए। छायादार और ठंडे स्थान में भण्डार नही करना चाहिए। अन्तिम तिथि के पहले प्रयोग करें। कटे-फटे पैकटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे किसान जैविक कृषि में अच्छा फसलों उत्पादन प्राप्त करने के लिए फस्फेट अवशोषक कल्चर जैव उर्वरक (वाम) एक अच्छे विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते है। फॉस्फेट अवशोषक जैव उर्वरक, वाम कल्चर को अपनाएं, कम लागत में फसल उत्पादन बढ़ाएं।

आशुतोष मिश्र
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, कृषि संकाय, म.गां.चि.ग्रा.विवि चित्रकूट, सतना

-ग्रामोदय विवि के कुलपति ने की विभागीय समीक्षा, बोले

गोद लिए पांचों गांवों में कृषि से जुड़े तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराएं

संवाददाता। चित्रकूट

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. भरत मिश्रा ने कृषि संकाय परिसर पहुंच कर अकादमिक विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर प्राकृतिक संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पावन सिरोठिया ने विभाग की आगामी कार्य योजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। फसल विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. सुधाकर प्रसाद मिश्र ने विभाग की प्रगति तथा आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। विभागाध्यक्ष प्रो. केके सिंह ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए प्रसार के आगामी कार्य योजना को प्रस्तुत किया। इस दौरान कुलपति प्रो. भरत मिश्रा ने संस्थापक कुलाधिपति भारत रत्न नानाजी देशमुख की परिकल्पना के अनुरूप कृषि संकाय को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए विवि द्वारा गोद लिए गए पांचों गांवों में कृषिगत योजनाओं को विस्तार से बताने के साथ ही तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बल दिया। समीक्षा बैठक में कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. डीपी राय ने कुलपति प्रो. मिश्रा का स्वागत किया। इस दौरान कृषि संकाय के प्राध्यापक प्रो. हरि शंकर कुशवाहा, डॉ. वाईके सिंह, डॉ. उमाशंकर मिश्र, डॉ. उमेश शुक्ला और डॉ. आलोक मालवीय मौजूद रहे।

किसानों प्राकृतिक खेती का आह्वान

इधर, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि के कृषि संकाय परिसर में कृषि विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा संचालित आत्मा परियोजना के अंतर्गत जालौन जिले से आए 36 किसानों के दल के किसान सदस्यों को आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। कृषि प्राध्यापक डॉ. वाईके सिंह ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वे प्राकृतिक कृषि अपना कर अपनी आय दुगनी करें। दो दिनों के लिए आए प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम में किसान दल का संयोजन आशा ग्रामोत्थान संस्थान उरई-जालौन ने किया है। ग्रामोत्थान संस्थान के राजेन्द्र सिंह ने संस्थान के कार्यों व कार्यक्रम की जानकारी दी।

कम लागत में अधिक कमाई, बढ़ रहा रुझान

लाल मूली की खेती अन्नदातों को कर रही मालामाल

संवाददाता। भोपाल

पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा आज के समय में किसान सब्जियों की खेती कर के भी अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी सब्जियों की खेती करने के इच्छुक हैं तो मूली की अच्छी किस्मों का चुनाव कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्नत किस्मों से अधिक उत्पादन तो मिलता ही है। साथ ही इनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है। यही कारण है कि बाजार में उचित भाव मिल जाता है। ठंड का मौसम हरी भरी और रंगीन सब्जियों के लिए जाना जाता है। इस समय में वातावरण में मौजूद नमी फसलों के बढ़वार में सहायक होती है। ऐसे में किसान अगर सही समय पर फसलों की बोवनी का काम करें तो बेहतर मुनाफा आसानी से ले सकते हैं। इस समय बाजार में मूली, गाजर, खीरा और पत्ता गोभी जैसी कई सब्जियां मिल जाती है, लेकिन अभी भी बाजार में लाल मूली कम ही दिखती है। किसान अगर इसकी खेती करें तो सामान्य मूली की तुलना में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

लाल मूली की खासियत

लाल मूली में सफेद की तुलना में अधिक एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जो इसकी मांग और दाम दोनों को बढ़ा देते हैं। यह समय लाल मूली की बोवनी के लिए उपयुक्त है। इस समय किसान लाल मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की यह किस्म लाल रंग की होती है। मूली की इस किस्म की बोवनी सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात यह है कि यह किस्म पूरे भारत में बोई जा सकती है। एक हेक्टेयर में बीजाई करने पर 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा मृदुला मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है। इसका रंग चमकीला लाल होता है। खाने में यह मुलायम होती है और इसका स्वाद कुछ तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बोवनी के 20 से 25 दिनों बाद यह किस्म तैयार हो जाती है।

बैतूल की महिलाओं ने किसानों से सीखी उन्नत खेती

संवाददाता। मंडला

आजीविका मिशन महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और नाबार्ड की वित्त पोषित सतपुड़ांचल प्रोड्यूसर कंपनी बैतूल के 28 किसानों का दल तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। जिसमें जिले के एक जिला एक उत्पाद कोदो-कुटकी के गतिविधियों, नवीन तकनीक एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम प्रशिक्षण सह-शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में सहभागिता दी। बताया गया कि नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य है महिला किसानों के द्वारा अपने क्षेत्र में उपजाई जाने वाली कोदो-कुटकी की फसल में नवीन तकनीक एवं इसके प्रसंस्करण मूल्य वर्धन, मार्केट लिंकेज आदि जानकारी को प्राप्त करना। इसे अपने क्षेत्र के

किसानों के साथ व्यवसायिक स्तर पर अपनाना। रंजीत कछवाहा ने बताया महिला किसानों की सहभागिता में पिछले दस वर्षों से कोदो-कुटकी, गुड़ सुंगंधित चावल, दाल आदि बहुत से उत्पाद के उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केट लिंकेजेस के लिए नियमित कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश के बाहर भी विक्रय किया जाता है। बैतूल से आए 28 किसानों के दल को स्थानीय बीआरसी भवन में आयोजित मीटिंग में नाबार्ड डीडीएम अखिलेश वर्मा ने जरूरी जानकारी दी। मिथला केवट के गांव में जाकर उन्हीं के खेत में मसाला गुड़ निर्माण इकाई में की बारीकियां समझीं। उसकी पैकिंग और प्रदेश के बाहर भी विक्रय किए जाने की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनकर प्रेरणा मिली। उन्हीं के द्वारा उत्पादित काला गेहूं एवं जैविक सब्जी के भोजन को दिखाया गया। राजीव कालोनी स्थित शहद प्रसंस्करण इकाई का भ्रमण किया। वहां निर्मित महुआ लड्डू, आंवला केंडी, अलसी आदि उत्पाद की जानकारी महिला सदस्यों को दी गई। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में लक्ष्मी भांवरे, मिथला केवट, कंचन पटेल, सुमन मरकाम, जमना नंदा, दिलीप केवट, दीप्ति मरावी, निशार कुरैशी आदि का सहयोग रहा।

पूर्व विधायक सत्यभानू चौहान ने किसानों से किया आह्वान

किसान सस्ती खेती के लिए जैविक खेती अपनाएं

संवाददाता। श्योपुर

किसान सस्ती खेती के लिए जैविक खेती अपनाएं। यह रासायनिक खेती के मुकाबले कम खर्चीली, टिकाऊ और स्वस्थ प्रक्रिया है। इसमें रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खरपतवारनाशी दवाओं के स्थान पर जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बात पूर्व विधायक सत्यभानू चौहान ने आयोजित प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित किए गए किसान सम्मान समारोह के दौरान कही। जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा ने कहा कि, परंपरागत साधनों और विधियों में भी कृषि वैज्ञानिकों ने कई नए आयाम जोड़े हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल से भरपूर खेती का लाभ ले सकते हैं। इससे भी अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसमें खाद के रूप में किसान गोबर खाद, मटका खाद, हरी खाद, केंचुआ खाद, नाडेप खाद आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाद खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और जैव विविधता को बचाती है। ये रासायनिक खाद के मुकाबले सस्ती है। इसे आप अपने ही खेतों में भी तैयार कर सकते हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक और सही समय पर खाद प्राप्त कर सकते हैं। यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

जैविक खेती से भविष्य भी सुरक्षित

जैविक खेतों की मिट्टी और पानी को यह जहरीला नहीं बनाती। जब जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो केवल इस मौसम के लिए सुरक्षित खेती कर रहे होते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी अपने खेत की मिट्टी, पानी और हवा को भी जहरीला होने से बचाते हैं। कार्यक्रम को किसान नेता रहिशंकर पालीवाल, देवीराम जाट, पूर्व मंडी अध्यक्ष काशीराम सेंगर ने भी किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया।

रात को विशेषकर तीसरे व चौथे प्रहर में पाला पड़ने की ज्यादा संभावना

टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह

पाले के नुकसान से फसलों को बचाने के लिए खेत में करें हल्की सिंचाई

नीरज जैन। टीकमगढ़

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़ द्वारा जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि शीतलहर और पाले से फसल की सुरक्षा के उपाय करें। रबी की फसलों को शीतलहर और पाले से काफी नुकसान होता है। जब तापक्रम 5 डिग्री से कम होने लगता है तब पाला पड़ने की पूर्ण संभाना होती है। हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाए। दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए तथा आसमान साफ रहे या उस दिन आधी रात से ही हवा रुक जाए तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे प्रहर में पाला पड़ने की संभावना रहती है। साधारणतया तापमान चाहे कितना ही नीचे चला जाए। यदि शीत लहर हवा के रूप में चलती रहे तो कोई नुकसान नहीं होता है। परन्तु यही इसी बीच हवा चलना रुक जाए तथा आसमान साफ हो तो पाला पड़ता है जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। जब भी पाला पड़ने की संभावना हो या मौसम पूर्वानुमान विभाग से पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई दे देनी चाहिए। जिससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

सिंचाई करने से 5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मे बढ़ोतरी हो जाती है। पाले से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है। नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जिससे सतह का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे पाले से बच जाते हैं। पॉलीथीन की जगह पर तिरपाल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

किसान खेत में करें धुआं

पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों का दक्षिण पूर्वी भाग खुला रहे, ताकि पौधों को सुबह व दोपहर को धूप मिलती रहे। अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए आप अपने खेत में धुआं पैदा कर दें जिससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता और पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। जिस दिन पाला पड़ने की संभवना हो उन दिनों फसलों पर गंधक के तेजाब के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए। इस के लिए एक लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टर क्षेत्र में प्लास्टिक के स्प्रेयर से छिड़कें। ध्यान रखें कि पौधों पर घोल की फुहार अच्छी तरह लगें।

फफूंदनाशी दवाओं का करें उपयोग

एसिफेट या मिथाइल डेमेटान क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। सरसों में प्रमुख रोग चूर्णिल फफूंदी के नियंत्रण के सल्फर और मृदुरो मिल के लिए कॉपर युक्त फफूंदनाशी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। चने में इल्ली की प्रथम अवस्था पर ही छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए क्विनालफास या प्रोफेनोफास की 2 मिली मात्र 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। गेहूं में किसान जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं वह सिंचाई के 2 दिन बाद करना चाहिए। जब खेत में पानी की मात्रा कम हो तब सिंचाई के पहले या साथ नहीं करना चाहिए। इस मौसम में पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए पाले से फसलों को बचाने के लिए खेत का तापमान नियंत्रण सिंचाई करना जरूरी रहता है।

दो सप्ताह में दिखेगा असर

छिड़काव का असर दो सप्ताह तक रहता है। यदि इस अवधि के बाद भी शीत लहर व पाले की संभावना बनी रहे तो गंधक के तेजाब को 15.15 दिन के अंतर से दोहराते रहें। सल्फर पाउडर को 3 किलो 1 एकड़ में छिड़काव करने के बाद सिंचाई करें या सल्फर पाउडर को 40 ग्राम प्रति पम्प,15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फसलों को बचाने के लिए खेत की उत्तरी-पश्चिमी मेड़ों पर तथा बीच-बीच में उचित स्थानों पर वायु अवरोधक पेड़ जैसे शहतूत, शीशम, बबूल, खेजड़ी अरडू और जामुन आदि लगा दिए जाएं तो पाले और ठंडी हवा के झोंको से फसल का बचाव हो सकता है।

वैज्ञानिक दल ने किया निरीक्षण

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों के दल ने ग्राम हसागोरा मे सुरेश कुशवाहा, जगदीश राय सहित 15-20 किसानों के खेतों में सरसों, चना, गेहूं सहित सब्जियों के खेतों पर भ्रमण और निरीक्षण करके मौसम के अनुसार समसामयिक कृषिगत आवश्यक कार्यों को किसानों को करने के लिए बताया। इस समय कोहरे की धुंध और मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण सरसों में प्रमुख कीट माहू, चितकबरा बाग, आरा मक्खी एवं पत्ता गोभी की तितली के द्वारा फसलों को हानि पहुंचाने से बचाने के लिए माहू कीट के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 7 मिली मात्रा 15-20 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

-कृषि केंद्र बड़वानी की पहल का दिखने लगा असर

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने पर बड़वानी से कम हुआ पलायन

संवाददाता। बडवानी

विगत एक दशक से आदिवासी बाहुल्य आंकाक्षी जिला बड़वानी में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि गांवों में कृषि जोत छोटे होने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकतर ग्रामीण रोजगार की तलाश में समीपस्थ राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं। कृषिविज्ञान केंद्र बड़वानी के द्वारा इस दिशा में ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर उनके कौशल उन्नयन के लिए अपने प्रशिक्षणों व विस्तार गतिविधियों के माध्यम से फसलों की उन्नत खेती एवं फल-सब्जियों की खेती में नवीनतम तकनीकी जैसे मलचींग, ड्रिप सिचांई, स्टेंकिग, ट्रेंनिग, खाद-उर्वरक प्रबंधन व सब्जियों की रोपाई-तुड़ाई आदि का प्रचार-प्रसार कर खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यत: सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने से वर्षभर खेती से संबधित कार्य स्वयं के खेत पर उपलब्ध रहता है। जिले में उद्यानिकी फसलें-फल-सब्जियों के रकबे में वृद्धि होने से अधिक कार्य दिवस कार्य उपलब्ध रहता है। कैलाश द्वारा वैज्ञानिकों की सलाह पर कपास, सोयाबीन, ज्वार एवं मुगंफली के साथ

लगभग आधे बीघे में खरीफ प्याज की फसल ली गयी थी । जिसमें उन्होनें 20 क्विंटल प्याज का उत्पादन प्राप्त कर 23 रुपए प्रति किलो की दर से खेत से ही विक्रय कर 46000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की। साथ ही उन्होंने कुछ क्षेत्र में टमाटर और मिर्च की फसल से भी आय प्राप्त की तथा कपास का 11 क्विंटल प्रति एकड़ व सोयाबीन 8.3 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया। कैलाश ने बताया कि कृषिविज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के डॉ. एसके बड़ोदिया, डॉ. डीके जैन व डॉ. डीके तिवारी के मार्गदर्शन में बकरी पालन के साथ-साथ मुर्गीपालन करने से वर्षभर घर पर ही कार्य उपलब्ध होने के कारण बाहर पलायन कर कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती और वैज्ञानिक विधियों से खेती करने पर लागत में कमी आती है जिससे मुनाफा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ही मेरे अन्य साथीयों द्वारा भी वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए समन्वित कृषि प्रणाली जिसमें फसलों की खेती के साथ सब्जी वर्गीय फसलों को जोड़कर घर में मुर्गीपालन, बकरी पालन और दुधारू पशु रखकर खेती की जा रही है। परिणाम स्वरूप उन्हें भी अन्यत्र कार्य नहीं तलाशना पड़ता है व अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। जिससे उनकी भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

पशु पालक और डेयरी संचालक जरूर लगवाएं टीका

पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नि:शुल्क ब्रूसेलोसिस टीकाकरण अभियान शुरू

संवाददाता। भोपाल

नव वर्ष के प्रथम दिन भारत सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल द्वारा नि:शुल्क ब्रूसेलोसिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भीमावत डेयरी फार्म मिसरोद से किया गया। इस अवसर पर जेएन कांसोटिया अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा उन्होंने पशु पालकों एवं डेयरी व्यवसायियों को अवगत कराया कि ब्रूसेलोसिस बीमारी एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि पशुओं के साथ-साथ मनुष्य को भी प्रभावित करती है। ग्याभिन पशुओं में इससे अबॉर्शन हो जाता है और पशु जल्दी-जल्दी ग्याभिन नहीं हो पाता है। जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। अभियान एक माह तक संचालित किया जाएगा एवं प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड के गोवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं के 4 से 8 माह के बीच के मादा बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा।

कार्यक्रम को डॉ. आरके मेहिया, संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा बताया गया कि समस्त पशुपालक एवं डेयरी व्यवसायी अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं टीकाकरण से या लाभ होगा कि गर्भधारण करने पर 7 से 8 माह के बीच गर्भपात की बीमारी नहीं होगी एवं यह बीमारी दूध के माध्यम से इंसानों में नहीं पहुंच पाएगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. अजय रामटेके, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं भोपाल द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुंहपका एवं खुरपका बीमारी एवं ब्रूसेलोसिस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही नि:शुल्क ब्रूसेलोसिस टीकाकरण अभियान 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक सतत जारी रहेगा।

चीतलों को लाने की शुरू की तैयारियां, वाहनों से होगा परिवहन, स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया जारी

माधव नेशनल पार्क से एक हजार चीतल जाएंगे कूनो

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क से एक हजार चीतल कूनो नेशनल पार्क में नए मेहमान के रूप में एक भेजे जाने वाले हैं। चीतलों को वाहनों के जरिए यहां लाया जाएगा। इसके लिए अनुमति जारी हो गई है। चीतलों को विधिवत स्वास्थ्य परीक्षण के बाद यहां लाया जाएगा, ताकि उनके जरिए यहां के चीतलों में किसी तरह की कोई बीमारी न फैल सके।

चीतलों को कूनो पार्क में लाए जाने के लिए पार्क प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी से चीते लाए जाने की तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में एक टीम ग्वालियर से दक्षिण अफ्रीका जाने वाली थी। मगर ओमिक्रॉन के कारण टीम का दौरा कैंसिल हो गया। अब टीम का अफ्रीका जाने का दौरा फिर से बनेगा। लेकिन कूनो में चीतों को लाए जाने की तैयारियां चल रही है। यहां उनके सुरक्षा इंतजामों सहित उनके भोजन की व्यवस्था भी जुटाई जा रही है। इसके लिए माधव नेशनल पार्क से एक हजार चीतलों को कूनों में लाया जा रहा है।

बताया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक आलोक कुमार ने माधव नेशनल पार्क से एक हजार चीतलों को कूनों में लाने की अनुमति जारी कर दी है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जो चीतल कूनों में लाए जाएंगे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। बिना स्वास्थ्य परीक्षण किसी भी चीतल को कूनो में न लाया जाए। इन निर्देशों के बाद माधव नेशनल पार्क की टीम ने चीतलों को स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया गया है।

कूनो पार्क में मौजूद वन्य जीव एक नजर में

चीतल	27253
सांभर	27809
नीलगाय	5661
चिंकारा	7585

नोट- यह जानकारी वर्ष 2018 की है।

माधव नेशलन पार्क से एक हजार चीतल स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कूनो नेशनल पार्क में भेजे जाएंगे, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है।
सीएस निनामा, सीसीएफ एवं संचालक सिंह परियोजना शिवपुरी

20 लाख से खरीदा गया विशेष वाहन

कूनो नेशनल पार्क में चीतों सहित अन्य वन्य जीवों के परिवहन के लिए एक विशेष वाहन खरीद लिया गया है। करीब 20 लाख की लागत से खरीदा गया वाहन बीते रोज कूनो वन मंडल श्योपुर के पास पहुंच गया है। जिसका विधिवत लोकार्पण श्योपुर दौरे पर आए सीसीएफसीएस निनामा के द्वारा किया गया। इस वाहन का उपयोग भी माधव नेशनल पाकज़ से चीतलों को लाने के लिए किया जाएगा। जरूरत लगने पर अन्य वाहनों का उपयोग भी चीतलों के परिवहन के लिए किया जाएगा।

कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में स्वच्छता पखवाड़े का समापन

गांव में स्वच्छता का जगाया अलख

संवाददाता। शिवपुरी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान क्षेत्र-9, जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में 16 से 31 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अंतिम दिन कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी में स्वच्छता पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रतिदिन अलग-अलग थीम के साथ ग्रामीण, शहरी, पर्यटन एवं अन्य स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियों के तहत साफ सफाई का महत्व और बेकार को बेहतर कैसे बनाने की विधा में वर्मीकम्पोस्ट निर्माण, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए घरेलू सामग्री को भी शहरी क्षेत्र में भी अपघटन करने के लिए जैव उर्वरकों अथवा प्रेरकों के द्वारा बताया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गाजरघास नियंत्रण, शहरी क्षेत्रों में पॉलीथीन फ्री तथा जन सामान्य को जंकफूड उपयोग नहीं करने तथा मोटे अनाजों को आहार में शामिल करने का आह्वान किया गया। इस अभियान में शपथ दिलाते हुए इस ओर भी प्रेरित किया गया कि कृषक अथवा कृषक

महिलाओं, छात्र-छात्राओं के साथ साथ सभी नागरिकों को स्वच्छता अभियान अंतर्गत साफ-सफाई रखने के लिए घरों, शासकीय भवनों अस्पतालों, पार्कों, जल स्त्रोतों तथा अन्य सभी जगह स्वय प्रेरणा से सफाई के लिए आगे बढ़-चढकर कार्य करना जरूरी है।

इनकी रही सहभागिता

केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.एसपी सिंह तथा कृषि विज्ञान केन्द्र की पूरी टीम डॉ.एमके भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.शैलेन्द्र सिंह कुशवाह, वैज्ञानिक डॉ.पुष्पेन्द्र सिंह, डॉ.एएल बसेडिया, तकनीकी अधिकारी नीरज कुशवाहा, कार्यालय अधीक्षक सतेन्द्र गुप्ता, शोध सहायक विजय प्रताप सिंह, स्टेनो आरती बंसल एवं नीतू वर्मा के साथ-साथ कृषक, छात्र-छात्राओं सहित कुल 487 नागरिकों की सहभागिता रही है।

नव वर्ष पर कृषि संगोष्ठी का आयोजन

किसानों को बताई जीवामृत बीजामृत बनाने की विधि

नीरज शर्मा। भिंड

भिंड जिले के कृषि विज्ञान केंद्र लहार द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में डॉ. पुनीत कुमार राठौर, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न गावों से 75 पुरुष और महिला किसानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर डॉ. अवधेश सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए जीवामृत और बीजामृत बनाने की विधि बताई गई। जीवामृत बनाने में गौमूत्र, गाय का गोबर, गुड़, चने का आटा और खेत की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बीजामृत बनाने के लिए इसी सामग्री के साथ-साथ केवल चूना का उपयोग किया जाता है। डॉ. सिंह द्वारा कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) के महत्व, संचालन की विधि भी उपस्थित कृषकों को बताई। इस अवसर पर उपस्थित सभी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा रहे संबोधन को सुना।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किसानों एवं कृषक उत्पादक संघ को पीएम किसान योजनांतर्गत 10वीं किस्त की राशि उनके खाते में डाली। अंत में उपस्थित किसानों का आभार कृषि विज्ञान केन्द्र के गौरव राजपूत, स्टेनोग्राफर ने व्यक्त किया।

एनटीपीसी लगाएगा देश का पहला प्लांट, नए साल में प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास

विकास की राह पर काशी, कूड़े-कचरे से बनेगा कोयला

संवाददाता। वाराणसी

पुरातन काया के साथ आधुनिक विकास में मॉडल बन रही काशी अब देश को कचरे से कोयला बनाना सिखाएगी। एनटीपीसी के सहयोग से नगर निगम रमना में प्रतिदिन 200 टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला प्लांट लगाने की तैयारी में है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के प्रस्तावित काशी दौरे में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। करीब 25 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट में निकलने वाले अवशेष को भी निस्तारित करने की वैज्ञानिक व्यवस्था होगी। बिजली उत्पादन इकाइयों में कोयला संकट से निजात के लिए वाराणसी में होने वाला यह प्रयोग देश को नई दिशा दिखाएगा।

20 एकड़ में प्लांट बनाया जाएगा – रमना में चयनित 25 एकड़ जमीन में 20 एकड़ में प्लांट बनाया जाएगा और पांच एकड़ में कोयला निर्माण के दौरान निकलने वाले अवशेष को वैज्ञानिक विधि से निष्पादित किया जाएगा। बनारस में प्रयोग सफल होने के बाद देश के कई शहरों में इसे स्थापित करने की योजना है। इस प्लांट को लगाने से पहले दादरी में हुए अध्ययन के अनुसार 600 टन कचरे से 200 टन कोयला बनाया जाएगा।

रमना एसटीपी प्लांट

रमना प्लांट का निर्माण अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन शहर से 600 टन कचरा निकलता है। शहर विस्तार के बाद करीब 800 टन कचरा निकासी का अनुमान है। इसलिए प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 800 टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी।

दादरी में लगाया डेमो प्लांट

एनटीपीसी के दादरी में इसका डेमो और टारफेक्शन प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह किस तरह पर्यावरण संरक्षण के साथ संचालित किया जाएगा। गंधहीन इस प्लांट में उत्सर्जन और शोर सीमा मानदंडों के अनुरूप होगी। हानिकारक पदार्थों के निर्वहन को रोकने के लिए कचरा लीचेट उपचार प्रणाली (जमीन में गड्ढा खोदकर निस्तारण करने की विधि) से गुजरेगा। स्वचालित मशीनों के जरिए इस प्लांट का संचालन किया जाएगा।

छह रुपए किलो कोयला

प्लांट की योजना के अनुसार एक किलोग्राम कोयला बनाने में छह रुपए का खर्च आएगा। जबकि बाजार में कोयले की कीमत कई गुना ज्यादा है। इस प्लांट के संचालन के बाद न केवल शहर में बढ़ रहे कचरे के ढेर से निजात मिलेगी, बल्कि इसका उपयोग भी किया जा सकेगा।

निर्माण करने वाली कंपनी दो साल तक इसका संचालन करने के बाद नगर निगम को सौंपेगी। कचरे से कोयला बनाने के प्लांट की टेंडर आदि प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। प्लांट के शिलान्यास की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल एक साल में प्लांट को संचालित करने की योजना है।
अजय कुमार, अधिशासी अभियंता, नगर निगम, वाराणसी

बीहड़ की ऊबड़-खाबड़ जमीन को किया समतल, खेती को बनाया लाभ का धंधा

आधुनिक तकनीक से बीहड़ में खेती का खर्च घटा, उत्पादन 20 फीसदी बढ़ा

-45 गांवों में 50 हजार बीघा खेत कंप्यूटरीकृत चाटी से सपाट

अवधेश डंडोतिया। मुरैना

आधुनिक तकनीक से खेती किस तरह आसान और लाभ का धंधा बन सकती है, यह मुरैना जिले के 45 से ज्यादा गांवों के किसानों ने साबित कर दिखाया है। इन किसानों ने कंप्यूटरीकृत चाटी (लेजर लैंड लेवलर) से बीहड़ की ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया तो सिंचाई में 20 प्रतिशत पानी और बिजली 15 प्रतिशत तक बचने लगी। खेतों से खरपतवार नष्ट हो गए और फसलों का उत्पादन भी 20 प्रतिशत तक बढ़ गया।

जिले के किसानों को तकनीक से खेती की राह दिखाने में आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना ने महती भूमिका निभाई। अनुसंधान केंद्र ने साल 2017 में फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत जौरा ब्लाक के सांटा गांव को चुना। इस गांव के आठ किसानों की जमीन को अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटरीकृत चाटी से सपाट किया गया। इससे जुताई, सिंचाई, बोवनी, खाद देना आसान हुआ और समतल हुए खेतों में गेहूं, बाजरा और सरसों जैसी फसलों की पैदावार आसपास के खेतों से ज्यादा हुई।

750 किसान आए आगे

यह देख हड़बांसी, अधन्नापुरा, पलपुरा, बसई, लालबांस, बिसंगपुरा, छैरा, चचियापुरा सहित करीब 45 गांवों के 750 से ज्यादा किसानों ने 50 हजार बीघा (10,000 हेक्टेयर) से ज्यादा जमीन कंप्यूटरीकृत चाटी से समतल की। कई किसानों ने खुद की कंप्यूटरीकृत चाटी खरीद ली है तो कई भाड़ा देकर जमीनों को समतल करा रहे हैं।

बीच खेत में लगता है लेजर

पूर्व में किसान बैलों से पटेला (मोटी सपाट लकड़ी) को बांधकर खेतों को समतल करते थे। इसके बाद ट्रैक्टरों में आगे व पीछे की चाटियों का चलन आया, लेकिन इनसे जमीन पूरी तरह सपाट नहीं हो पाती थी। कंप्यूटरीकृत चाटी से एक इंच की ऊंचाई तक का फर्क मिट गया। इसके लिए एक लेजर बीच खेत में खड़ा किया जाता है, उससे खेत का लेबल तय होता है। यह लेबल कंप्यूटर में फीड किया जाता है। उसके बाद लेजर व कंप्यूटर से कनेक्ट ट्रैक्टर में पीछे लगी चाटी खेत को समतल करती जाती है।

समतल खेत बने फायदेमंद

पहले खेत के निचले स्तर की तरफ खाद की मात्रा बढ़ जाती थी, क्योंकि पानी के बहाव में खाद बहकर चली जाती थी और खरपतवार पनपता था। सपाट खेतों में खरपतवार की समस्या खत्म हो गई। खेत समतल हुए सिंचाई जल्दी होने लगी, जिससे सिंचाई में खर्च होने वाला पानी 20 प्रतिशत तक कम हो गया। वहीं मोटर कम चलने से 15 प्रतिशत तक बिजली की खपत घट गई।

बीहड़ क्षेत्र व चंबल नदी किनारे के गांवों में अधिकांश खेत ऊंचे-नीचे हैं। यहां किसानों ने पहल कर कंप्यूटरीकृत चाटी से 45 से ज्यादा गांवों में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन समतल कर ली है। जमीनें समतल होने से सिंचाई, बिजली व किसान की मेहनत कम हुई। खरपतवार की शिकायत दूर हुई और पैदावार 20 प्रतिशत तक बढ़ गई।
-डॉ. संदीप सिंह तोमर, कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना

सब्जी की फसल पर दूसरे ने करा लिया धान का पंजीयन

सिवनी। घंसौर विकासखंड के ग्राम जामुनपानी (केदारपुर) में पटवारी ने जिस खेत में सब्जी की फसल लगाई गई है। उसमें धान दर्शा दिया है। उस जमीन पर तीन पीढ़ी से काबिज किसानों की जगह किसी और का नाम भी चढ़े होने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी के बाद किसानों ने कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखककर शिकायत किया है। कहा है कि ग्राम जामुनपानी पटवारी हल्का नंबर 67 ने खसरा नंबर 55 रकबा 0.100 हेक्टेयर, खसरा नंबर 65 रकबा 4.920 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 2.900 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 71 रकबा 1.720 हेक्टेयर की भूमि पर करीब तीन पीढ़ी से हमलोग काबिज है। लंबे समय से इस पर खेती कर गुजर-बसर कर रहे हैं। कुछ किसानों के पूर्वज की मौत के बाद उनके परिजन खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक रसूखदार ने उक्त खेत पर अपना नाम चढ़वा लिया है। उसने अपनी पहुंच के बल पर बिना फसल लगाए पंजीयन करा लिया है। किसानों ने खेत में लगाए गए फसल का पंचनामा और सीडी बनाकर शिकायत के साथ संबंधित अधिकारियों को सौंपा है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)